भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1963
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

जनजातीय व्यक्तियों के पैतृक भूमि संबंधी अधिकारों का संरक्षण

† 1963. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के नागरहोल से प्राप्त हाल की उन रिपोर्टों की जानकारी है जोकि जेनु कुरुबा जनजातीय परिवारों द्वारा पैतृक भूमि अधिकारों का दावा करने के कारण बेदखली नोटिस और विवाद से संबंधित हैं और यदि हां, तो उक्त घटनाक्रमों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जेनु कुरुबा परिवारों द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) दावों की संख्या कितनी है, तथा स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों की बेदखली के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) संरक्षण संबंधी प्रयासों में संतुलन बनाए रखते हुए संरक्षित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और आजीविका अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इसे 20 राज्यों (कर्नाटक सहित) और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कुल 52 जेनुकुरूबा परिवार विरोध प्रदर्शन करने और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकार जारी करने की मांग करने के लिए पोन्नमपेट तालुक के के. बडगा ग्राम पंचायत के तहत अत्तूर कोल्ली नामक वन क्षेत्र में आए हैं, जो नागरहोल बाघ अभयारण्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन परिवारों ने एफआरए के तहत दावे दायर किए, जिनमें से 39

दावों को पर्याप्त साक्ष्य/रिकॉर्ड की कमी के कारण ग्राम सभा स्तर पर खारिज कर दिया गया था, और शेष 13 दावे अभी भी आवेदनों की समीक्षा के लिए ग्राम सभा के समक्ष लंबित हैं। खारिज किए गए आवेदकों ने बाद में उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) के समक्ष अपील दायर की, हालांकि सभी 39 आवेदनों को सबूतों की कमी के कारण 22-05-2025 को आयोजित एक बैठक के माध्यम से एसडीएलसी द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दावेदारों को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के समक्ष अपील करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था। दावेदारों ने अब कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसडीएलसी के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। इसके अलावा, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग ने निदेशक और उप वन संरक्षक, नागरहोल बाघ अभयारण्य, हुनसुर से अनुरोध किया है कि इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक इन 52 जेनुकुरुबा परिवारों को बेदखल नहीं किया जाए। वर्तमान में, सभी 52 जेनुकुरुबा परिवार कोडागु जिले के वन क्षेत्र अत्तूर कोल्ली में रह रहे हैं।

(ख) जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, जेनुकुरुबा समुदाय के कुल दायर किए गए वन अधिकार दावे, वितरित अधिकार, अस्वीकार किए गए दावे और लंबित दावे इस प्रकार हैं:

व्यक्तिगतः

प्राप्त आवेदनों की संख्या	वितरित अधिकार पत्रो की संख्या	अस्वीकृत दावों की संख्या	लंबित दावों की संख्या
5993	1680	3953	360

समुदायिकः

प्राप्त आवेदनों की संख्या	वितरित अधिकार पत्रो की संख्या	अस्वीकृत दावों की संख्या	लंबित दावों की संख्या
139	72	50	17

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशानिर्देश जारी करता रहा है।

(घ) एफआरए के तहत, संरक्षण प्रयासों को संतुलित करते हुए संरक्षित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और आजीविका अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के भीतर अधिकार मौजूद हैं।
धारा 3 (1) के तहत वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को निवास और आजीविका के लिए वन भूमि और संसाधनों को रखने, रहने और उपयोग करने का अधिकार दिया गया

है, जिसमें पारंपरिक वनों पर सामुदायिक अधिकार और जैव विविधता एवं पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच शामिल है।

एफआरए की धारा 5 अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं और ग्राम संस्थानों को अधिकार देती हैः वन्यजीवों, वनों और जैव विविधता की रक्षा करना; जलग्रहण क्षेत्रों, जल स्रोतों और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना; और यह सुनिश्चित करना कि वन-निवासी समुदायों के निवास स्थान को, उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करने वाली विनाशकारी प्रथाओं से संरक्षित किया जाए। धारा 3 (1) (i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार आगे ग्राम सभाओं, वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को अपने पारंपरिक वनों की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं, जिससे समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण को सक्षम बनाया जा सकता है जो आजीविका को बनाए रखता है और वन के साथ सांस्कृतिक संबंधों की रक्षा करता है। इस मंत्रालय ने 12.09.2023 को सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, मंत्रालय ने जिला कलेक्टरों सहित जनजातीय कल्याण विभागों के राज्य अधिकारियों के साथ कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और विचार-विमर्श सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित किए हैं, जहां सीएसओ के सदस्यों को एफआरए की कार्यान्वयन प्रक्रिया को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ संरक्षण के प्रयासों को संतुलित करते हुए संरक्षित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और आजीविका अधिकारों की रक्षा की जा सके।

*****